



GENERAL STUDIES (Module – 5)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)-M-GS15

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Devendra Prakash meena

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: * 7102

Center & Date: Delhi & 29/07/19

UPSC Roll No. (If allotted): 1134510

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501, 8448485517

1. भारत में रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र को कौन-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? हाल के दिनों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये किये गए उपायों को गिनाइये। (150 शब्द) 10

What are the challenges facing the logistics sector in India? Enumerate the measures taken in recent times for giving a boost to this sector. (150 words) 10

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच एक कड़ी का कार्य करता है।

चुनौतियाँ

- अवसंरचनात्मक :- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास नहीं होना है। भारत में पर्याप्त मात्रा में Cold storage, Ware house, Fridged Truck आदि का अभाव है।
- तकनीकी :- तकनीकी पर विदेशी निर्भरता का होना भी बड़ी चुनौती है।
- विनीय :- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में विनियोग का अभाव है। साथ ही विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित नहीं कर पा रहा है।
- मानव संसाधन :- कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

बढ़ावा देने के उपाय

- सरकार द्वारा विन की कमी दूर करने हेतु तथा अतसंरचनात्मक ढाँचे के विकास के लिए इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे ऋण मिलने में सुविधा होगी।
- सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि के द्वारा इसमें निवेश आकर्षित किया जा रहा है।
- e-NWR के द्वारा ware house में बिना सामान ट्रांसफर के लाभ प्राप्त संभव है।

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि नॉजिस्टिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए सरकार ने इसके विकास के लिए पुरानी कदम उठाये हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

2. शैडो बैंकिंग प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? वर्तमान में भारत की शैडो बैंकिंग प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? (150 शब्द) 10

What do you mean by shadow banking system? What are the challenges faced by India's shadow banking system at present? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाराये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

शैडो बैंकिंग प्रणाली से तात्पर्य बिना बैंकिंग अतंरचना के बैंक साथी के माध्यम से विन्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

चुनौतियाँ

- पर्याप्त मानव संसाधन का अभाव - बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी है, जो बैंक साथी के रूप में कार्य कर सके।
- वित्त की कमी - वर्तमान में अधिकांश बैंक NPA की समस्या तथा बेसल मानकों को पूरा करने की प्रतिबद्धता से जूझ रहे हैं।
- जनता में जागरूकता का अभाव - अशिक्षा तथा जागरूकता के कारण जनता बैंक साथी के साथ विन्तीय लेनदेन में संकोच करती है।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केवल मात्र पर ध्यान दिये जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर दबाव की स्थिति है। जिसे

इसे अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता का संचार किया जाना चाहिए। इसके लिए नुरुकड नारक, मीडिया की सहायता ली जा सकती है।
- चूंकि विनीय समावेशन का होना एक अनिवार्यता के समान है। अतः इस दिशा में प्रयास किये जाने चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

3. भूमि उत्पादकता की बजाय सिंचाई जल उत्पादकता को प्राथमिकता देने की अपनी कुछ चुनौतियाँ हैं, जिन पर वर्तमान में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Shifting of priority from land productivity to irrigation water productivity has its own set of challenges which need to be addressed in time. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत में कुल जल का लगभग 80% तथा भूमिगत जल का 89% सिंचाई में उपयोग किया जाता है किन्तु इसकी उत्पादकता कम है।

ऐसे में जंगीर जल संकट के दौर में सिंचाई जल उत्पादकता अपना समय की मांग है किन्तु इसमें अनेक चुनौतियाँ हैं।

चुनौतियाँ

→ किसानों की समस्याएँ :-

- अधिकांश किसानों के पास पर्याप्त धन की उपलब्धता नहीं है, जो फल्लारा सिंचाई अथवा ट्रिप सिंचाई के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकें।
- भूमि का अलग-अलग जगह होना (अपखंडन) एवं जोत का छोटा आकार।
- ग्रामीण भारत में लगभग 56% किसान परिवार भूमिहीन हैं, जो कारखाने के स्थापित के आभाव में इस तरह का निवेश नहीं कर पाते।
- जीवन निर्वाह कृषि को महत्त्व देना।

→ संगठनात्मक चुनौतियाँ-

- पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषण का अभाव
- स्वदेशी तकनीकी का अभाव।

आगे की राह

- किसानों को ICT के माध्यम से नवीन तकनीकी की जानकारी प्रदान की जाये।
- किसान विज्ञान केन्द्र द्वारा किसानों को नवीन तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- भूमि सुधारों को लागू किया जाये ताकि उपविभाजन तथा अपखंडन व जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

4. मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? यह भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कैसे सहायता प्रदान कर सकता है? (150 शब्द) 10

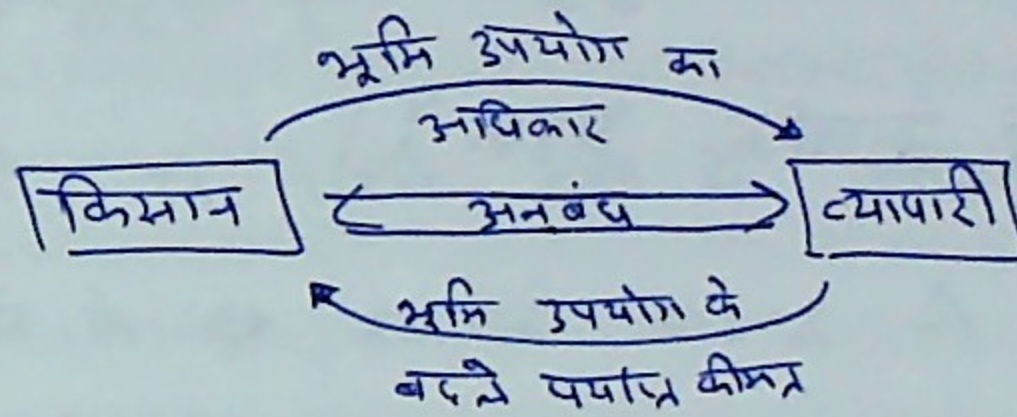
What are the key provisions of Model Agricultural Land Leasing Act 2016? How it can help in enhancing farm productivity in India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत में लगभग 85% किसान लघु एवं सीमान्त हैं, जिससे कृषि जीवन निर्वाह रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम, 2016 लाया गया।

अनुबंधित कृषि



अधिनियम के प्रावधान

- ↳ अनुबंधित कृषि से संबंधित मुद्दों को चिह्नित किया गया है।
- पचास दिशा निर्देश दिये गये हैं।
- राज्य सरकारों को नीतिगत लागू करने के लिए संशोधन का विकल्प।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने में लाभ

- भूमि के अपखंडन एवं छोटे खेत की समस्या का समाधान।
- निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याओं को हटाने का प्रयास।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यह अधिनिम्न किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

5. भारत के पहले मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम 'गगनयान' के उद्देश्यों और महत्व की चर्चा कीजिये। साथ ही उन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का भी विस्तृत वर्णन कीजिये जिन्हें भारत ने 'गगनयान' के लिये विकसित किया है। (150 शब्द) 10

Discuss the objectives and significance of India's maiden human spaceflight programme- 'Gaganyaan'. Also, enumerate the critical technologies India has developed for Gaganyaan. (150 words) 10

ISRO का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'गगनयान' 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजना है।

उद्देश्य

- इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य में अन्य ग्रहों पर अनुसंधान के लिए मानव भेजने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
- भारत को उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित करना, जो स्वयं के तकनीकी कौशल से अंतरिक्ष में पहुँचे हैं।
- तकनीकी प्रदर्शन करना

महत्व

- GSLV-MKII द्वारा किया जाने वाला यह कार्यक्रम अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहुँच मजबूत करेगा, जिससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त होगी।



→ इससे भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं का दोहन किया जा सकेगा।

→ ISRO का वैश्विक स्तर पर महत्व बढ़ने से विदेशी प्रक्षेपण से आय की प्राप्ति होगी।

प्रौद्योगिकियाँ जो विकसित की गईं

① GSLV - मकान के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन।

② अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी के लिए CARE (कू माइपल)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

6. व्यावहारिक अर्थशास्त्र भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान कर सकता है। व्याख्या कीजिये। (150 शब्द) 10

Behavioural economics can provide a valuable instrument for socio-economic change in India. Explain. (150 words) 10

ठम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

हाल में व्यावहारिक अर्थशास्त्र के लिए
सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री को नोबेल
पुरस्कार प्रदान किया गया।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र भारत में
सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन हेतु एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकता है।

उदाहरण

- ① 'बेटी बचाओं - बेटी पढ़ाओं' अभियान को सफल
बनाने के लिए संस्थागत प्रसव के लिए धनराशि
प्रदान करना, बेटी की शिक्षा के लिए विभिन्न
योजनाएँ, भविष्य के लिए सुक-या समृद्धि योजना,
Selfie with daughter आदि कार्यक्रमों द्वारा
लोगों की अनिच्छित परिवर्तन की गई।

- ② विनीय समावेशन के लिए पहले बैंकों तक
लोगों की पहुँच सुलभ की गई, तत्पश्चात् उन्हें

बीमा सुविधा , ऑवर डाफ्ट जैसे जोत्साहन
दिये । इससे सरकार के लीकेज में कमी हुई ।

③ कर अनुपातना में वृद्धि करने के लिए पहले

कर नियमों को आसान बनाया जाये । ताकि
लोगों तक पहुँच बढ़े । तत्पश्चात्, उन्हे विभिन्न
प्रकार के जोत्साहन द्वारा दायरे में लाया
जाये ।

सारांशतः स्पष्ट है कि व्यावहारिक
अर्थशास्त्र के माध्यम से लोगों की अक्रियता
में परिवर्तन कर , सामाजिक- आर्थिक विकास
को नवीन दिशा प्रदान की जा सकती है ।

7. आभासी मुद्राओं द्वारा प्रदत्त लाभ विवाद योग्य हो सकते हैं परंतु उनमें अंतर्निहित प्रौद्योगिकी में निश्चित रूप से उज्वल संभावनाएँ समाहित हैं। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

The benefits offered by virtual currencies may be debatable but the underlying technology behind them is certainly having bright prospects. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

आभासी मुद्राएँ वर्तमान में बैंक क्षेत्र में
प्रयुक्त की जा रही हैं किन्तु उनका बैंक क्षेत्र किसी
केंद्रीकृत बैंक द्वारा कंट्रोल नहीं है।

क्रिप्टोकॉइन्स के विवाद

- धनशोधन में प्रयुक्त
- टैरर फंडिंग
- डार्कनेट ट्रेडिंग (अवैध व्यापार)

किन्तु इसमें प्रयुक्त Block-chain
तकनीकी का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में संभव है।

Block-chain के लाभ -

- सूचनाओं का तीव्र संचार।
- गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखना।

8. विधिक प्रणाली को सुदृढ़ करना भारतीय नीति-निर्माताओं द्वारा किया जा सकने वाला सर्वोत्तम निवेश हो सकता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Strengthening the legal system may be the best investment Indian policymakers can make. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

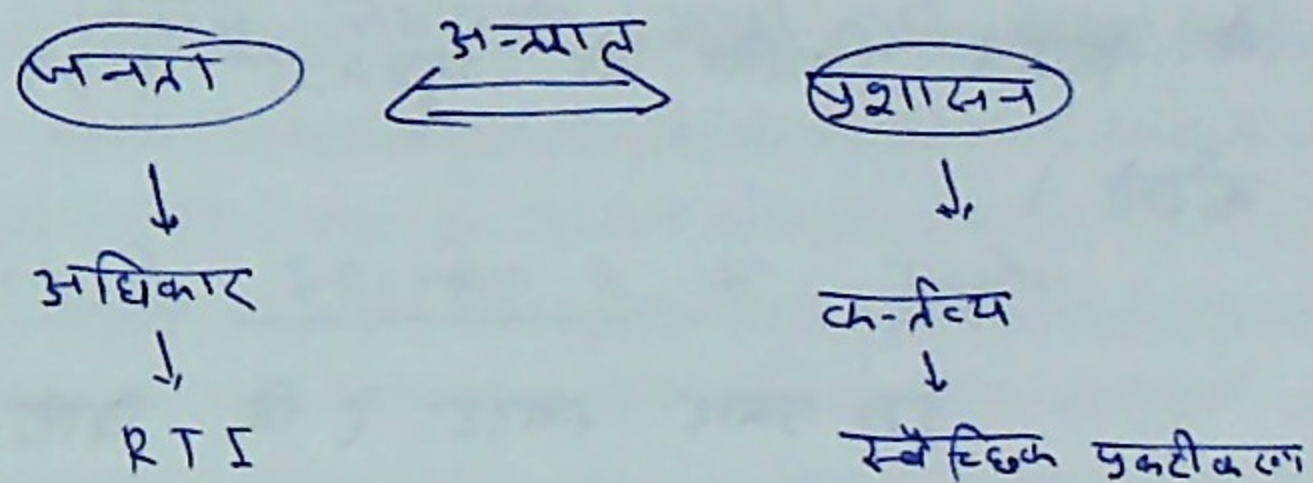
(Candidate must not write on this margin)

किसी भी कल्याणकारी राज्य का प्रमुख कार्य विधि के शासन को बनाये रखने हूये जनता तक सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।

वर्तमान में विधिक प्रणाली में अनेक कमियाँ उपस्थित हैं, जिसके कारण जनता तक लाभ नहीं पहुँच पाता।

→ नियमों की जटिल प्रकृति।

→ जन जागरूकता का अभाव। इसके मूचना अन्तराल बढ़ता है।

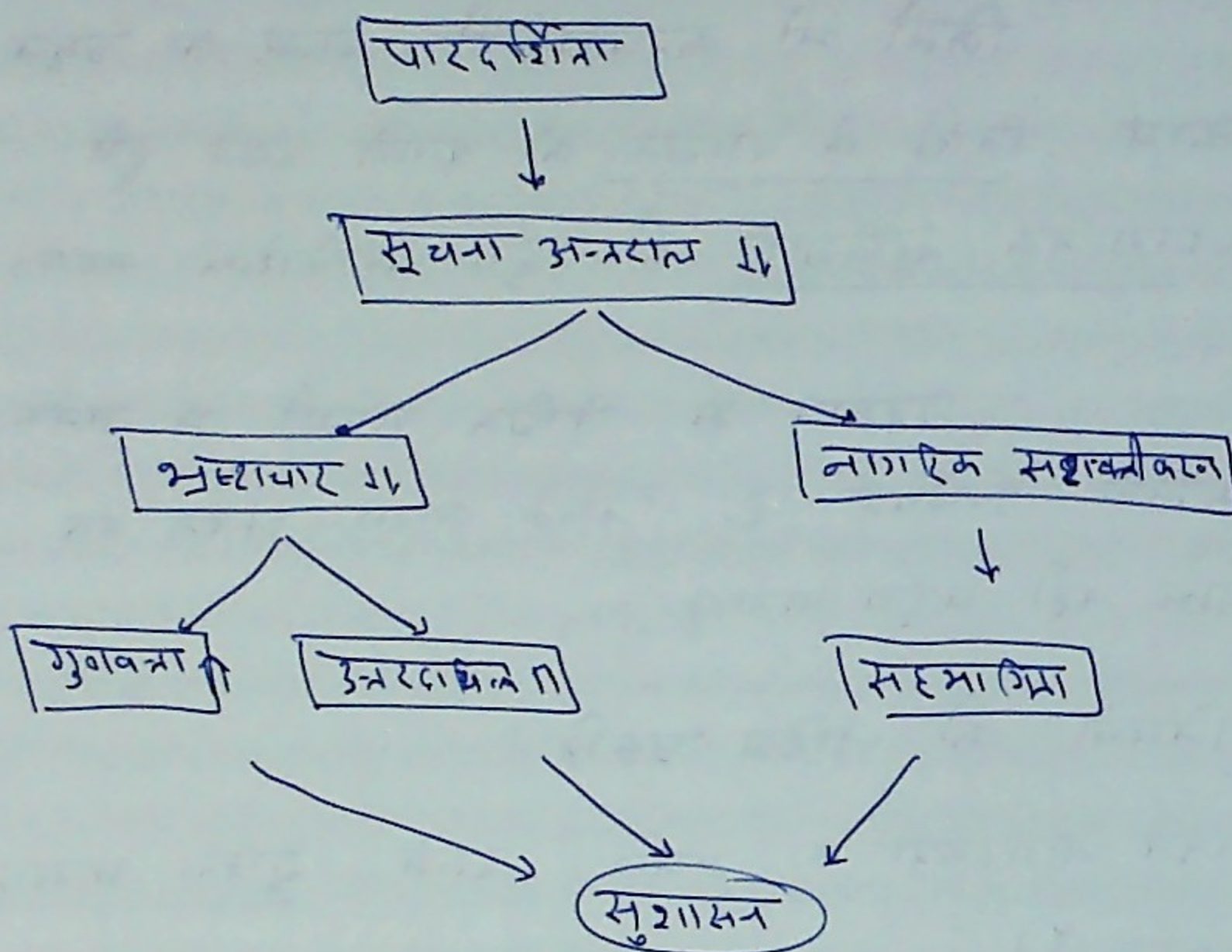


→ पब्लिक गिजेंस रिट्यून्स का मजबूत नहीं होना।

→ लाभपीताशाही तथा भ्रष्टाचार।

विधिक षणाली को सुदृढ़ करने के लाभ

→ पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।



→ ~~कि~~ नियमों की सुगमता FDI को आकर्षित करेगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विधिक षणाली में सुधार सुशासन की और एक कदम बढ़ाने के समान है।

9. भारत जैसी आकांक्षी अर्थव्यवस्था सरकार तथा केंद्रीय बैंक के बीच टकराव को सहन नहीं कर सकती है। इस संबंध में हाल की विकास गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

An aspiring economy like India can ill afford a tussle between the government and the central bank. Discuss in the context of recent developments. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

किसी भी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक एवं केंद्र सरकार के मध्य सहज समन्वय आवश्यक होता है क्योंकि नीति निर्माण एवं विकास में दोनों की भूमिका पूरक होती है।

टकराव के कारण

- सरकार द्वारा ब्याज दरों को कम करने के लिए RBI पर दबाव डालना।
- लाभान्श का हस्तांतरण करने के लिए टकराव।
- बैंकों को विशेष निगरानी सूची से बाहर करना।
- RBI Act के Section 7 का उपयोग

प्रभाव

- RBI द्वारा ब्याज दर कम नहीं करने के कारण MSME को ऋण प्राप्त में कठिनाई होना।

→ RBI की स्वायत्तता को कम करने के प्रयास से विदेशी निवेश प्रभावित होना।

चूंकि भारत जैसे राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए, उच्च विकास की ओर बढ़ना।

ऐसे में RBI तथा सरकार के मध्य सम्बन्ध ही मौद्रिक नीति के बेहतर क्रियान्वयन को सफल बना सकता है।

अतः आवश्यकता है, दोनों पक्षों के मध्य सम्बन्ध की, ताकि आर्थिक विकास के साथ मानव विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

10. संभावित साइबर हमलों के विरुद्ध भारत की तैयारी का मूल्यांकन कीजिये। इस संकट को रोकने के लिये किये जा सकने वाले कुछ संरक्षोपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

Evaluate India's preparedness against potential cyber attacks. Suggest measures that should be taken to tackle this threat. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

साइबर स्पेस को मुक्त सारण पहुँचाने
की दृष्टि से किये गये प्रयास, साइबर हमलों
की श्रेणी से अलग हैं।

भारत साइबर हमलों की दृष्टि से एक
संवेदनशील राष्ट्र है। ऐसे में भारत द्वारा एक
प्रभावी तैयारी की गई है।

सरकार के प्रयास

①

विधिक

- सूचना अधिनियम, 2008
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013

②

संस्थागत

- महत्वपूर्ण सूचना की रक्षा के लिए NCERT का गठन।
- गृह मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय साइबर सल्लाह
केन्द्र (NCCC) का गठन।
- MeitY के अन्तर्गत CERT - IN का गठन।
- निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा
सुरक्षित भारत 21 परियोजना

www.drishtiiias.com

Contact: 8750187501, 8448485517

Copyright - Drishti The Vision Foundation

अन्तर्राष्ट्रीय

- द्विपक्षीय सम्झौते | Ex - अमेरिका के साथ
- ब्रुजापेस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर।

प्रभावी उपाय

- रक्षात्मक की बजाय आक्रामक रणनीति अपनाना।
- विदेशी उपकरणों की प्रभावी जाँच।
- डाटा ऑपनिवेशीकरण से निपटना।
- प्रत्येक वेबसाइट के लिए साइबर आडिटिंग की व्यवस्था।

सारांश: कहा जा सकता है कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ सफल बनाने के लिए साइबर सुरक्षा अति आवश्यक है।

11. पिछले दो दशकों में भारत के उत्कृष्ट विकास के बावजूद निम्न भुगतान तथा वेतन असमानता समावेशी विकास को प्राप्त करने की राह में महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite India's outstanding growth in the last two decades, low pay and wage inequality remain serious obstacles towards achieving inclusive growth. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण जैसे आर्थिक सुधारों ने भारत को निम्न वृद्धि रूप से निकाशकर सर्वाधिक वृद्धि वाला राष्ट्र बनाया।

उत्कृष्ट विकास की स्थिति

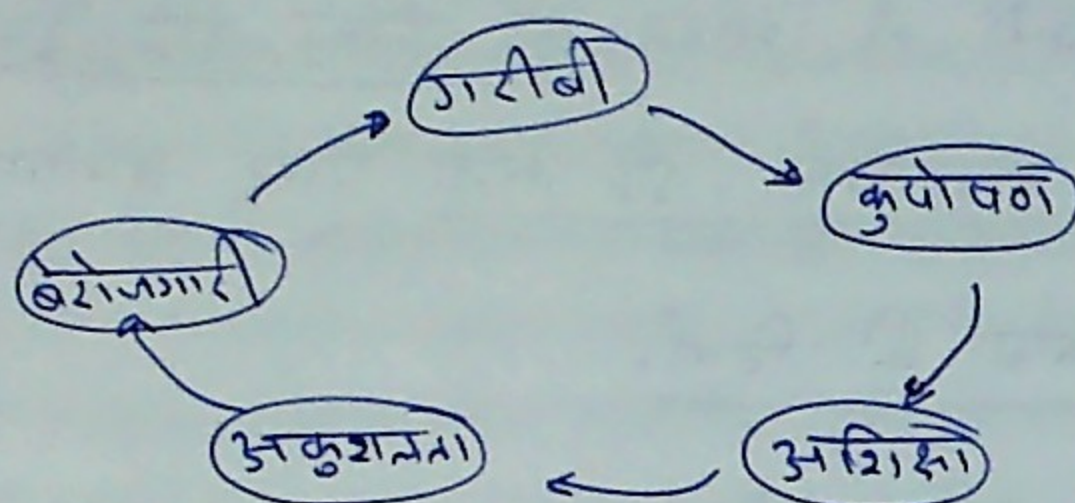
- भारत की प्रति व्यक्ति आय 11 हजार से बढ़कर वर्तमान में एक लाख को पार कर गई है।
- विदेशी निवेश आकर्षित करने में अग्रणी राष्ट्र
- विदेशी मुद्रा भंडार 400 बिलियन डॉलर से अधिक
- विदेशी निर्यात में वृद्धि।

युनौत्रियों

- ① निम्न भुगतान : नीति आयोग के अनुसार भारत की मूल समस्या बेरोजगारी की नहीं बल्कि अल्प रोजगार है। इसके कारण प्रतिभा का पलायन, पर्याप्त निवेश आय एवं वचन का अभाव, पर्याप्त निवेश नहीं हो पाया, जैसी युनौत्रियों का

सामना करना पड़ता है।

मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में रोजगार की
अधिकता के बावजूद निम्न भुगतान गरीबी
दुश्चक्र की निरन्तरता का कारण है।



②

वैतन असमानता - भारतीय संविधान में
समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है
किन्तु व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों
की तुलना में केवल 40-60% ही वेतन की
प्राप्ति होती है।

इससे अनेक प्रभाव सामने आते हैं -

- आर्थिक निर्भरता
- FLPR का कम होना।
- कार्यस्थल पर यौन शोषण।
-

जेंडर गैप इंडेक्स, 2018 में भारत

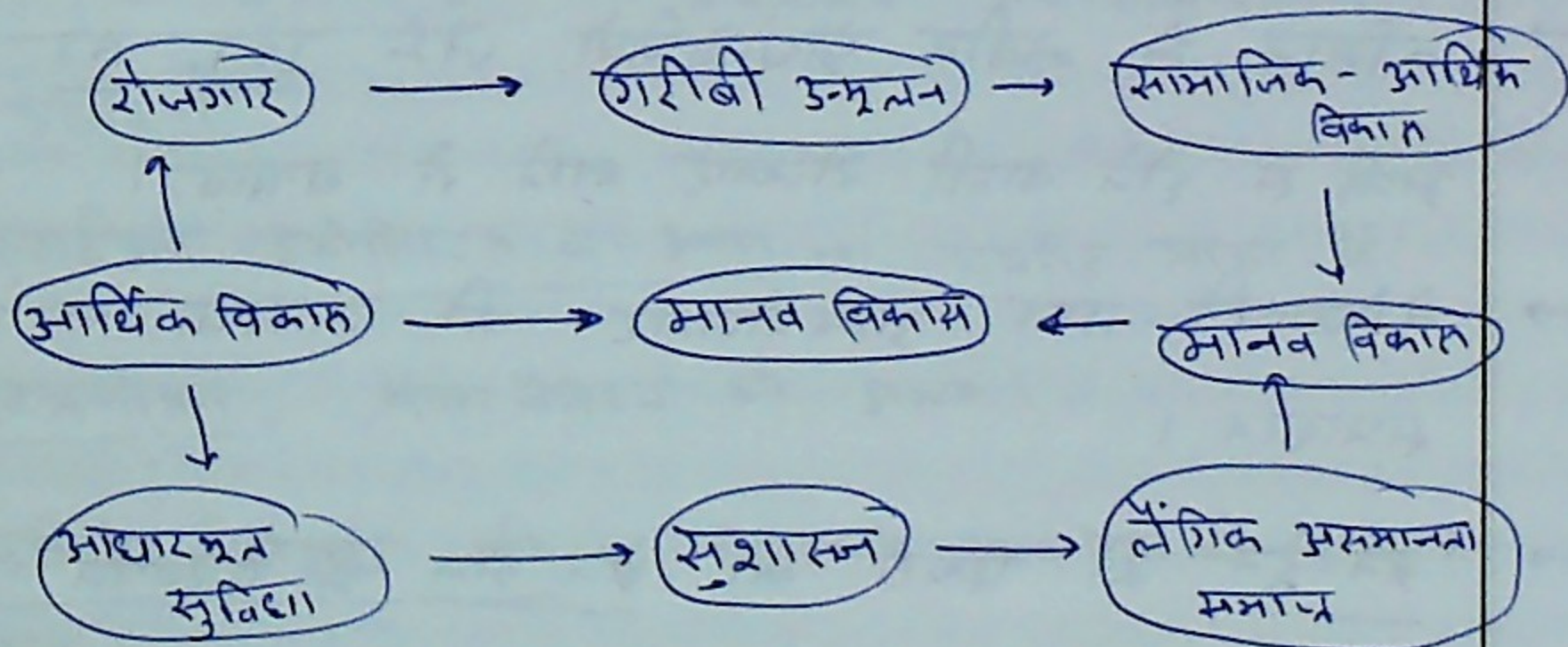
को आर्थिक सहभागिता में 149 देशों में 144 रैंक प्राप्त हुई है, जो वैश्व असमानता एवं निम्न भुगतान की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

आगे की राह

- संवैधानिक उपबंधों को कठोरता से लागू किया जाये।
- ~~समावेशी विकास बढ़े~~
- लैंगिक समानता वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- आर्थिक विकास को समावेशी विकास से संबद्ध किया जाये।





12. क्या भारत के बदलते रोजगार परिदृश्य में देश के युवाओं को रोजगार इच्छुक से रोजगार सृजक में परिवर्तित करना संभव है? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं? (250 शब्द) 15

Is it possible to transform India's youth from job seekers to job creators in the changing job scenario in India? What steps have been taken by the government to attain this objective?

(250 words) 15

विश्व बैंक के अनुसार 2005 से 2012 के मध्य भारत में केवल 3 मिलियन रोजगार परिवर्धन सृजित हुए जबकि आवश्यकता 13 मिलियन परिवर्धन की थी।

ऐसे में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में परिवर्तित करना आवश्यक है।

लाभ

- वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकियों जैसे IT, AI आदि से होने वाली रोजगार क्षति से बचाव।
- बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या का समाधान।
- ब्रेन ड्रेन की स्थिति को ब्रेन गेन में परिवर्तन
- आर्थिक विकास को तीव्र करने में सहायता

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

मिलेगी।

- युवाओं की रचनात्मकता का लाभ प्राप्त होगा।
- भविष्य की कंपनियों का मूलन वर्तमान स्टार्टअप से ही होगा।
- तकनीकी पर विदेशी निर्भरता समाप्त।

युनैत्रिप्पॉ

- मानव संसाधन → एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग आधे इंजीनियर गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते।
- निजी क्षेत्र द्वारा प्रोत्साहन नहीं → निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्थिति एवं टि्वन बैलेंस शीट समस्या।
- जटिल श्रम कानून → स्टार्टअप पर नकारात्मक प्रभाव।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम का अभाव → पर्याप्त मात्रा में वित्तपोषण, वेंचर कैपिटल का अभाव।
- उच्च शिक्षित कौशल नहीं :- विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम।

देश	दक्षिण कोरिया	जापान	USA	India
उच्च शिक्षित मनुष्य	96%	80%	52%	5.4%

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

सरकार के प्रयास

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना → औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
- स्टार्टअप इंडिया → युवाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान करना।
- स्टैंडअप इंडिया - SCIST समुदाय में उद्यमिता का विकास करना।
- प्रधानमंत्री बुढ़ा योजना → परामर्श मात्रा में बुढ़ा की सुविधा।
- भारतीय कौशल संस्थान -
- अटल इनोवेशन मिशन

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि भारत का विकास युवाओं के द्वारा ही संभव है। अतः डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

13. वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध में भारत को कौन-सी नीति तथा शासन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? इन बाधाओं को संबोधित करने हेतु कुछ विशेष उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 15

What are the policy and governance constraints faced by India in doubling farmers' income by 2022? Suggest few specific measures to address these constraints. (250 words) 15

भारत सरकार द्वारा किसानों की द्रिधिति में सुधार करने तथा कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान बढ़ाने के लिए 2022 तक आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

किये गये प्रयास

- (1) अवसंरचनात्मक :- किसानों तक पर्याप्त सिंचाई सुविधा के लिए PMKSY, असड़क कनेक्टिविटी के लिए PMBSY, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए PMSSY PMKSY को लागू किया है।
- (2) तकनीकी एवं विनीय :- नवीन तकनीकों पर अनुदान, किसान विज्ञान केन्द्र, जायफिकता क्षेत्र क्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास।
- (3) पर्याप्त MSP प्रदान करना।
- (4) लागत कम करने के लिए गोबरघन योजना, कुसुम योजना, किसान सम्मान निधि।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

→ उचित मूल्य प्राप्ति के लिए ई-नाम, गायीन
होर बाजार का विकास, PM-AASHA आदि।

पुनर्निर्माण

- ① कृषि राज्य सूची का विषय होने के कारण विद्यार्थी स्पष्ट नहीं है और केन्द्र सरकार के प्रयासों का पूर्णतः लाभ किसान तक नहीं पहुँच पाता।
- ② किसानों की आय दुगुना करना तथा मुद्रास्फीति को कम बनाये रखना के प्रत्यक्ष दुंद की विद्यार्थी।
- ③ भूमि सुधारों का लागू नहीं हो पाता।
- ④ किसानों तक प्रशासन की पहुँच नहीं हो पाता जिससे जानकारी का अभाव।
- ⑤ MSP का लाभ केवल 6% किसानों को ही प्राप्त पाता है।
- ⑥ लघु एवं सीमान्त किसानों की अधिकता।
- ⑦ तकनीकी के प्रयोगों को प्रोत्साहित करना किन्तु 52% किसान परिवार अज्ञान हैं।

उपाय

- राज्यों द्वारा APMC एक्ट के स्थान पर APLM एक्ट को अपनाना।
- अनुबंधित कृषि को प्रोत्साहित करना।
- लागत कम करने के लिए जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।
- किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलें उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि निर्यात द्वारा अधिक लाभ।
- ICT का बेहतर उपयोग करना। किसान कॉल सेंटर, किसान विज्ञान केन्द्र द्वारा आपदाओं की पूर्व जानकारी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि केन्द्र तथा राज्य के मध्य आपसी संवाद इस नीतिगत तथा शासन संबंधी चुनौती को दूर कर सकता है।

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

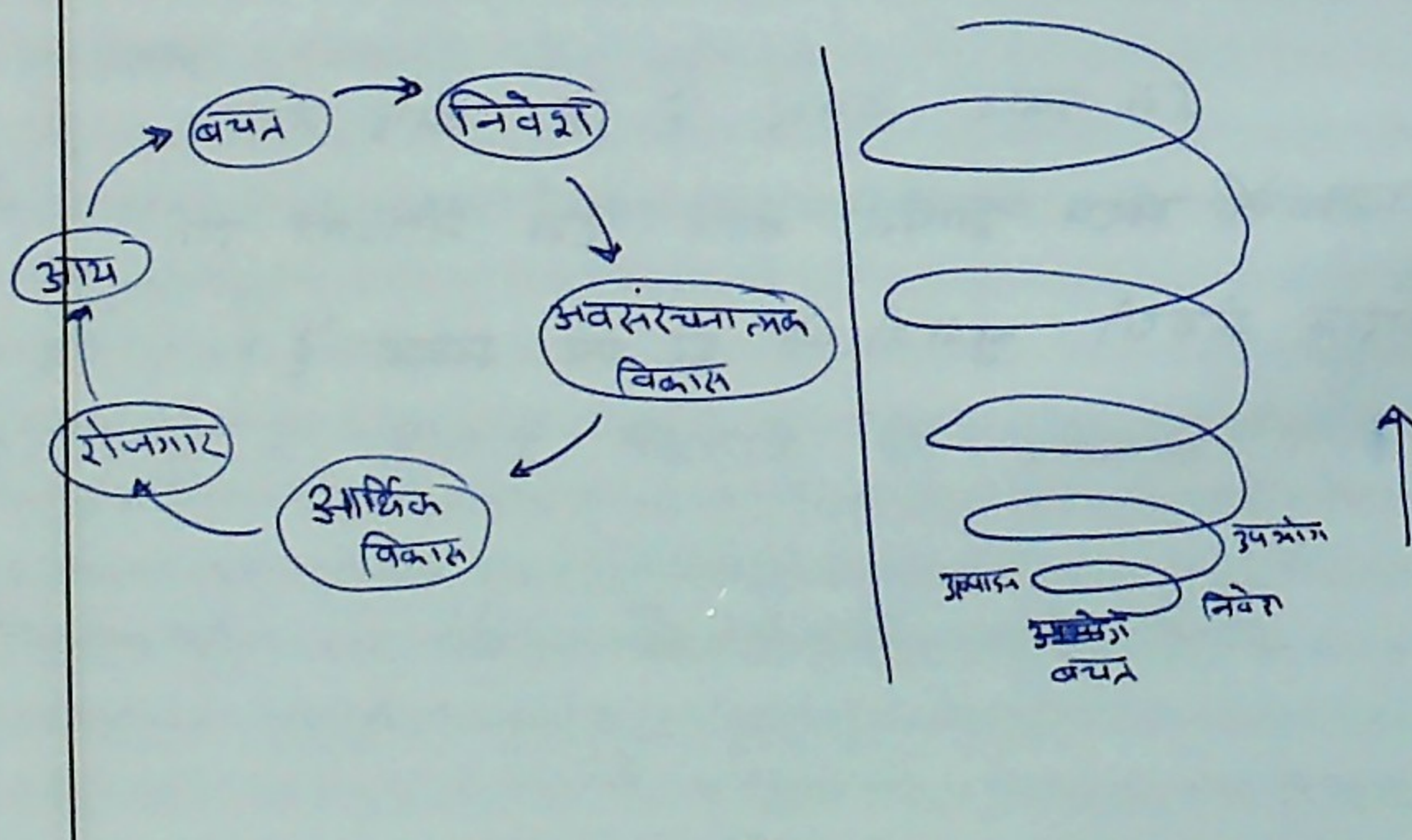
14. 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य को लक्षित करने के लिये बचत, निवेश एवं निर्यात का एक सुदृढ़ चक्र अतिआवश्यक है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

To achieve the objective of becoming a USD 5 trillion economy, a virtuous cycle of savings, investment and exports is required. Comment. (250 words) 15

हाल ही में बजट में भारत को ~~200~~ पाँच वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ~~के~~ अर्थव्यवस्था के सूत्री क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश के द्वारा विकास की आवश्यकता है। इसके लिए एक विकास चक्र को लक्षित करने की आवश्यकता है।

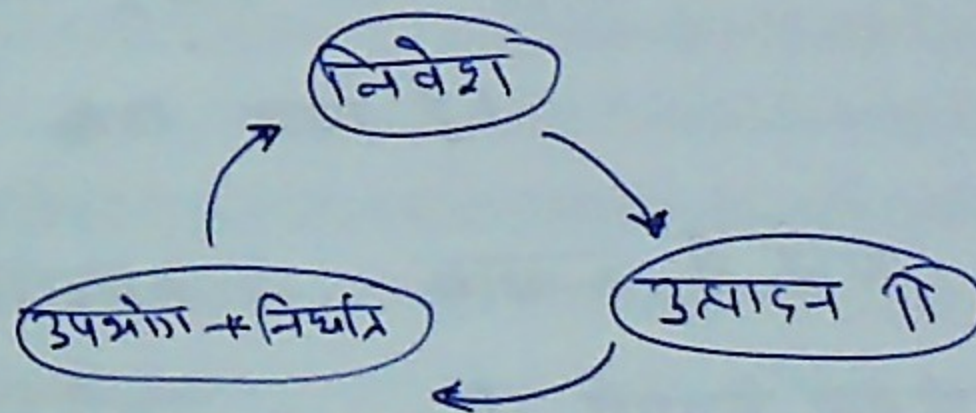
विकास चक्र एवं वर्तुलाकार संवृद्धि



किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए धारित निवेश
स्वतंत्रिक महत्वपूर्ण होता है। धारित निवेश नागरिकों
द्वारा की गई वचन के समानुपाती होता है।

नागरिकों की वचन उनकी आय के
समानुपाती होती है। नागरिकों की आय राष्ट्रीय
आय पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय में
वृद्धि करने के लिए ~~उपभोग को~~ उत्पादन एवं
उपभोग में वृद्धि आवश्यक है।

अतिरिक्त उत्पादन का नियंत्रण कर इससे
प्राप्त आय का निवेश कर पुनः उत्पादन में
वृद्धि की जा सकती है।



सरकार द्वारा किये जाये प्रयास

→ जन धन योजना के माध्यम से विनीय समावेशन
द्वारा लीकेज में कमी।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

- सुकन्या समृद्धि खाता योजना ।
- MSME क्षेत्र को ऋण सुविधा (1 मिनट में एक करोड़ का लोन)
- ~~क्षेत्र~~ सेक्टर स्पेशलिज्ड विकास योजनाएँ
- मानव संसाधन का विकास करना ।
- विदेशी निवेश (FDI) को जोत्साहित करना ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास एक प्रक्रिया की भाँति है, जिसमें बचत व निवेश के द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर निर्यात संभव है।

15. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये। साथ ही किस प्रकार यह नीति भारतीय जैव ईंधन नीति के पूर्व संस्करण का उन्नत प्रारूप है, का परीक्षण भी कीजिये।

(250 शब्द) 15

Discuss the salient features of the National Policy on Biofuels 2018. Also, examine how this policy is an improvement over the earlier biofuel policy of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

सतत विकास लक्ष्यों (SDG-7) की प्राप्ति एवं पेरिस सम्मेलन के INDC की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जैव ईंधन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जैव ईंधन को प्राथमिकता देने हुये सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय नीति जारी की गई।

विशेषताएँ -

→ इसमें जैव ईंधन को स्रोत के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है।

- प्राथमिक - खाद्यान्न से प्राप्त
- द्वितीयक - गैर खाद्यान्न फसलों से प्राप्त
- तृतीयक - डोंगलों से प्राप्त

→ जैव ईंधन पर शोध एवं अनुसंधान के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है।



→ अपशिष्ट खाद्य तेलों से जैव ईंधन बनाये जाने को भी सम्मिलित किया गया है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

write on this margin

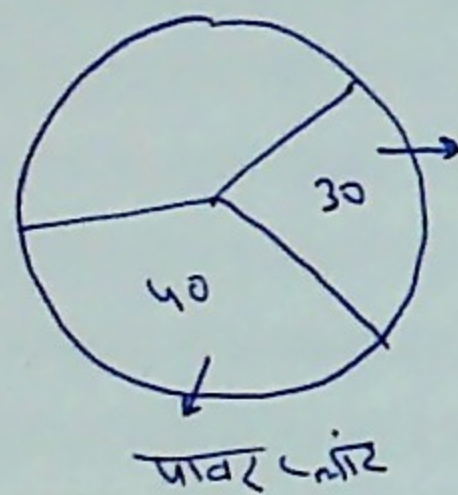
16. भारतीय शहरों में न्यून-कार्बन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता तथा चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में किये गए उपायों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the necessity and challenges of a low-carbon transport system in Indian cities. Mention the recent measures taken by the government in this regard. (250 words) 15

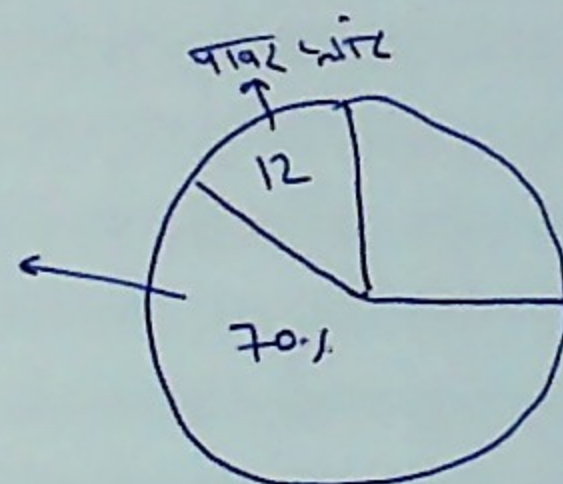
भारतीय शहरों में अधिकांश प्रदूषक (PM, CO_2) का मुख्य स्रोत ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही है। ऐसे में शहरों को गैस चेंबर बनने से रोकने के लिए न्यून कार्बन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर की प्रदूषण में भूमिका

CO_2 उत्सर्जन



PM पार्टिकल



आवश्यकता

- शहरों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
- प्रदूषण के कारण कार्यक्षमता में कमी, GDP को प्रभावित करती है।

- लगातार बढ़ता शहरीकरण, इससे नगरीय उत्सर्जन क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- पेरिस सम्मेलन के INDC की प्रति के लिए
- सतत विकास लक्ष्यों की प्रति के लिए।

इसके अतिरिक्त वाहनों से उत्सर्जित NO_2 , SO_2 ~~अम्लीय वर्षा~~ अम्लीय वर्षा तथा ओजोन छूटना का कारण बन रहे हैं।

चुनौतियाँ

- पर्याप्त मात्रा में तकनीकी नहीं :- सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास के बावजूद वहनीय तकनीकी का अभाव है। लीथियम के रूप में कच्चे मात्रा की कमी।
- अवसंरचनात्मक ढाँचा :- ई-वाहनों के लिए चार्लिंग स्टेशन, CNG वाहनों के लिए CNG स्टेशन की कमी।
- नीतिगत अस्पष्टता :- सरकार द्वारा एक और ई-वाहनों की प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं अधिक लागत इसे वहनीय नहीं बनाती।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

→ जन जागरूकता :- जनता के मध्य ई-वाहनों के प्रति जागरूकता का अभाव।

सरकार के प्रयास

- (1) FAME योजना - इसके द्वितीय चरण के अन्तर्गत 10 हजार करोड़ के जोरदारन द्वारा लागत कम करके तथा मांग उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (2) ई-वाहनों पर GST कम करना - सरकार द्वारा ई-वाहनों पर GST 18% से कम करके 5% करना
- (3) सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना
- (4) जैव ईंधन तथा एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा
- (5) LNG का प्रयोग

इस प्रकार स्पष्ट है कि अविलंब के वहीय एवं सतत परिवहन का आधार न्यूज कार्बन परिवहन प्रणाली है, अतः इस दिशा में शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है।

17. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल शाब्दिक रूप से राजकोषीय सावधानी देखने को मिली, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Enactment of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act has brought the Indian economy on the path of fiscal prudence only in letter but not in spirit. Critically analyse. (250 words) 15

सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए संसद द्वारा वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया।

उद्देश्य

- राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु 3% से कम करना।
- राष्ट्रीय राजस्व घाटे को शून्य करना।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना।

अधिनियम की प्रभाविता

- इस अधिनियम के द्वारा राजस्व घाटे के शून्य का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
- राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु वर्तमान

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)



में 3.31 - 3.21 के दायरे में लाया गया है, जो एक सफलता है।

एस्कैप ब्लॉज एवं N.K. Singh पैरल :-

→ चूंकि निजी क्षेत्र द्वारा कम निवेश किये जाने के कारण राजकोषीय घाटे की स्थिति अभी भी लक्ष्य से उपर बनी हुई है। इस स्थिति में सरकार यदि लक्ष्य प्राप्ति पर कल देगी तो सार्वजनिक निवेश में कमी होगी।

इसी स्थिति को देखते हुये 0.5.1 का एस्कैप ब्लॉज का प्रावधान किया गया है।

FRBM एक्ट की असफलता :-

- राज्यों की वित्तीय स्थिति लगातार निम्न बनी हुई है।
- राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की प्राप्ति की परिष्कृत सरकार को सार्वजनिक निवेश कम करने के लिए बाध्य करती है।

सारांशतः स्पष्ट है कि FRBM एक्ट अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आंशिक रूप से सफल रहा है तथा सरकार द्वारा 2022 तक 3% बजट के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास लगातार जारी हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

18. वामपंथी अतिवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा संकट बना हुआ है। सुस्पष्ट कीजिये। साथ ही इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों की भी विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Left-Wing Extremism (LWE) remains a major threat to the internal security of the country. Elucidate. Also, discuss various measures taken by the government for addressing this issue. (250 words) 15

वामपंथी अतिवाद एक विचारधारा आधारित आन्दोलन है, जो संविधान एवं विधि के शासन की अवहेलना करते हुए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश करता है।

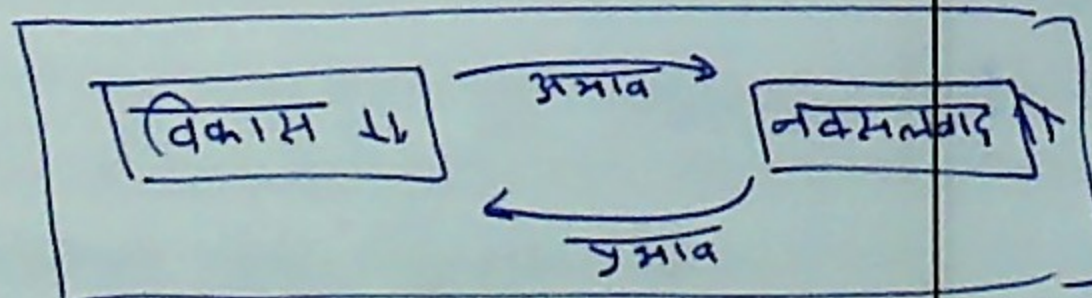
LWE का प्रभाव

- हाल ही में जारी रिपोर्ट (गृह मंत्रालय) के अनुसार LWE वर्तमान में 90 जिलों में फैला हुआ है तथा 8 नवीन जिले इसमें सम्मिलित हुए हैं।



- दक्षिण भारत की ओर LWE का प्रसार एक चिंता का विषय है।

LWE की ^{निम्नता} ~~उच्चता~~ के कारण



- (1) भूमि संबंधी कारण :- जनजातियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार प्रदान नहीं करना।

- (ii) प्रशासनिक कुशलता → प्रशासन द्वारा जनजातियों के शोषण को नहीं रोक पाया। इनका पुनर्वास।
- (iii) आजीविका संबंधी - रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं।
- (iv) संकट की निरन्तरता का एक कारण जनजातियों में व्याप्त अशिक्षा तथा जागरूकता का अभाव है।
- (v) Local Intelligence का अभाव।

सरकार के प्रयास

सरकार द्वारा विकासत्मक तथा रक्षामुक्त दोनों स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं।

(1) विकासत्मक

- सड़क आवश्यकता योजना के द्वारा कनेक्टिविटी
- मोबाइल टावर योजना के द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी
- शिक्षा - स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास
- कौशल विकास हेतु रौंगरी योजना।
- अधिकार प्रदान करना।

- FRA, 2006
- PESA, 1996

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

② रक्षात्मक

→ स वस्त्ररिया वरालिपन, ओपरेशन जे हाउण के
द्वारा ।

→ सैन्य बलों का आधुनिकीकरण ।

→ आत्म समर्पण

→ लोकल इंटेलेजेंस

→ SAMADHAN

हाल ही के वर्षों में सरकारी ~~संस्था~~
योजनाओं का नाम दिखाई पड़ रहा है। आत्म समर्पण
करने की दर में ५१% की इडि हुई है, जबकि
घरनाओं में १३% की कमी आई है। अतः
सरकार को दोनों स्तर पर कार्य करने की
आवश्यकता है।

19. भारतीय रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण कई संकटों का हल प्रदान कर सकता है। हालाँकि राह उतनी आसान नहीं है जितनी प्रतीत होती है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Indigenising the Indian defence sector can address multiple woes, however road is not as easy as it seems. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत विश्व का सर्वाधिक सैन्य आयात
करने वाला राष्ट्र है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र का
स्वदेशीकरण आयात निर्ररता में कमी तथा राष्ट्रीय
सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लाभ

- आयात निर्ररता में कमी - बजट का एक बड़ा भाग इस पर खर्च होता है, जिसका उपयोग सामाजिक निवेश पर किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा - विदेशी आयातित उपकरणों की जानकारी निर्ररत करके वाले राष्ट्र के पास होती है। साथ ही हाल ही में स्कोपीन पनडुब्बी का डर्रा लीक होने जैसी घटनाएं कम होंगी।
- रोजगार - रक्षा क्षेत्र के विकास से भारत में अधिक मात्रा में रोजगार पैदा किये जा

सकते हैं।

→ विदेशी मुद्रा की जाप्री - निर्यात के द्वारा
विदेशी मुद्रा की जाप्री भी संभव है।

→ स्थानीय समस्याओं के अनुरूप तकनीकी विकास

भारत के विस्तृत एवं विविध भौगोलिक क्षेत्रफल के लिए विदेशी उपकरण महत्व नहीं है।

चुनौतियाँ -

(1) ~~क्षेत्र~~ शोध व अनुसंधान पर खर्च कम बर्च करना।

देश	खर्च	USA	China	India
% GDP पर	4.3%	2.8%	2.2%	0.8%

(2) तकनीकी पर विदेशी निर्भरता।

(3) निजी क्षेत्र की भूमिका का कम होना।

(4) पर्याप्त अवसरवात्मक ढाँचे का अभाव।

(5) कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन नहीं।

- ~~लिखें~~
→ पेटेंट संबंधी विवाद ।

आगे की राह

- रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाये।
→ स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाये। इसके लिए
इंस्टी - यूनीवर्सिटी लिंकेज की व्यवस्था।
→ ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पर्याप्त फैनोसिप

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उसके सैन्य बलों पर निर्भर करती है। अतः आवश्यक है कि रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण किया जाये।

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

20. भारत में विधिक तथा संस्थागत तंत्र मौजूद होने के बावजूद नीति निर्माताओं के लिये आपदा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite legal and institutional mechanisms in place, disaster management continues to pose a daunting challenge for policymakers in India. Critically evaluate. (250 words) 15

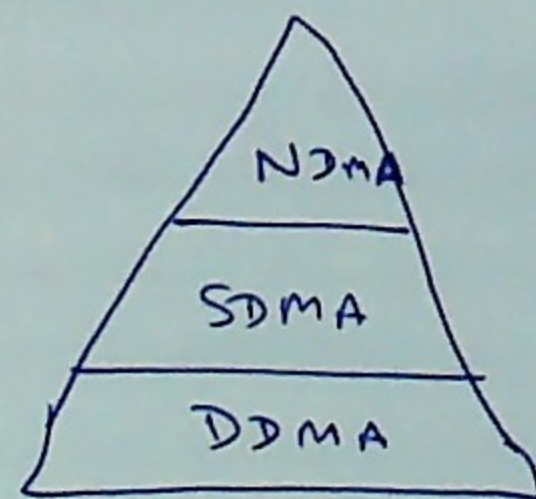
आपदा प्रबंधन से तात्पर्य शमन, तैयारी, अनुकूलता तथा राहत को समझना पूर्वक एकीकृत करते हुए जोखिम प्रत्याख्यान का विकास करना है।

भारत में विधिक तंत्र

- (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- (2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009
- (3) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016
- (4) सेंडर्स फ्रेमवर्क

संस्थागत तंत्र

- (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- (2) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- (3) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- (4) आपदा राहत प्रभाग (गृह विभाग)



चुनौतियाँ

- NDMA द्वारा लागू की गई अधिकांश योजनाएं अभी विकासधीन हैं अथवा अपूर्ण हैं।
- NDRF में 27% पद रिक्त हैं।
- NDMA के तहत 3 महीने में बैठक का आयोजन है किन्तु यह लागू नहीं हो पा रहा है।
- कुशल मानव संसाधन एवं तकनीकी का अभाव।
- जनता के स्तर पर जागरूकता का अभाव।
- स्थानीय परम्परागत ज्ञान का उपयोग नहीं करना।
- आपदाओं की नवीन प्रवृत्तियाँ।

Ex - फॉर्जि चक्रवात मानसून पूर्व

आगे की राह

आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण में सभी हितधारकों - सरकार, संजवन तथा समुदाय के मध्य सम-वय आलोक है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं चाहिये। (Candidate n write on this

